



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1992 (अग्रहायण 14, 1914)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1992 (AGRAHAYANA 14, 1914)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	876
भाग II—खण्ड 2—	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1277
भाग I—खण्ड 3—	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	13
भाग I—खण्ड 4—	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	2133
भाग II—खण्ड 1—	अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—	अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—	विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—	उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—	भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—	भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—	उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1207
भाग III—खण्ड 2—	पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1395
भाग III—खण्ड 3—	मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—	विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3841
भाग IV—	गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	185
भाग V—	अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

CONTENTS

PAOR	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	875
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	1277
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2133
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1207
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1395
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3841
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies	185
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

(इलैक्ट्रॉनिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1992

विषय : इलैक्ट्रॉनिक हाईवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी) योजना— अन्तर्मन्त्रालयी स्थायी समिति का गठन।

सं० 15(100)/90-नियति—1. इलैक्ट्रॉनिक हाईवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी) योजना के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय (भारत सरकार) के दिनांक 14-9-1992 की अधिसूचना सं० 42 (एन 8)/92-97 के अनुसरण में एक अन्तर्मन्त्रालयी स्थायी समिति का गठन करने का निर्णय किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

- | | |
|--|---------|
| (i) सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग | अध्यक्ष |
| (ii) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय | सदस्य |
| अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | |
| (iii) सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, | सदस्य |
| उद्योग मंत्रालय अथवा औद्योगिक | |
| अनुमोदन सचिवालय द्वारा नामित | |
| अधिकारी | |
| (iv) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय | सदस्य |
| अथवा सीमा-शुल्क विभाग द्वारा नामित अधिकारी | |
| (v) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय | सदस्य |
| अथवा ई सी बी द्वारा नामित अधिकारी | |
| (vi) आर्थिक सलाहकार, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग | सदस्य |
| (vii) संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन प्रभाग | सदस्य |
| इलैक्ट्रॉनिकी विभाग | |

2. यह योजना इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ई एच टी पी के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थापना करने अथवा ई एच टी पी के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक इकाई की स्थापना करने या ई एच टी पी के रूप में एक अलग इकाई की स्थापना करने के लिए एक आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के पास भेजा जा सकता है।

3. यह अन्तर्मन्त्रालयी स्थायी समिति निम्नलिखित कार्यों को करेगी :—

- ई एच टी पी की स्थापना के लिए सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करना तथा भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना।
- ऐसे मामलों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना जो वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं० 42 (एन 8)/92-97 में विनिर्दिष्ट नहीं है, लेकिन जो ई एच टी पी के प्रचालन के लिए अनिवार्य है।

(iii) ई एच टी पी योजना के अन्तर्गत इकाइयों के लिए इकरार-नामा अवधि का निर्धारण करना तथा वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं० में निर्धारित डि-बाँडिंग के आवेदन-पत्रों पर विचार करना।

(iv) ई एच टी पी योजना को लागू करने/निर्णय लेने में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों/मामलों का समाधान करना।

4. अन्तर्मन्त्रालयी स्थायी समिति की बैठकें नियमित अवधि में अर्थात् महीने में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय अपने विवेकानुसार अनिश्चित बैठकों का आयोजन कर सकते हैं।

5. सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अन्तर्मन्त्रालयी स्थायी समिति प्रभावी हो जाएगी।

6. यह अधिसूचना सार्वजनिक हित में जारी की जा रही है।

नी० गोपालस्वामी
संयुक्त सचिव
इलैक्ट्रॉनिकी विभाग

(मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 नवम्बर 1992

सं० 14(5)/ई 92-एस टी क्यू सी/एस एम्यू क्यू ए—इलैक्ट्रॉनिकी विभाग इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण की एक योजना शुरू करने के प्रश्न पर विचार कर रहा था। इस विषय में उठाये गये एक कदम के रूप में सरकार ने आई एस ओ-9000 मानकों के अनुरूप इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण योजना (एस क्यू योजना) को अनुमोदित कर दिया है। मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय, जो इलैक्ट्रॉनिकी विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रमाणीकरण निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा महानिदेशक (मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय) इस प्रमाणीकरण निकाय के पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रमाणीकरण निकाय में एक अधिशासी बोर्ड होगा, जिससे योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देने, समीक्षा करने तथा नीतिगत निर्णय लेने के लिए सभी संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अमरनाथ शर्मा
उप निदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1992

सं० फा० 11(1)/88-वि०सं०स्की० का० सं०—उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति तारीख 9 जुलाई, 1991 के एक संकल्प द्वारा गठित की गई थी।

और तारीख 22-11-1981 की अधिसूचना द्वारा, उपर्युक्त संकल्प के अनुसरण में वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति 1-11-1991 से एक वर्ष की अवधि के लिए या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, बनाई गई थी।

और उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की अवधि 31-10-1992 को समाप्त हो गई है।

अतः अब, राष्ट्रपति, तारीख 22-11-1991 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में, वर्तमान उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की अवधि, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्याय-मूर्ति श्री पी०वी० सावंत की अध्यक्षता में, 1-11-1992 से एक वर्ष की और अवधि के लिए या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के अनुसार उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति गठित किए जाने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाते हैं।

चि० प्रभाकर राव,
विशेष सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1992

आदेश

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आर-28 (अपतट) के 160.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ-12012/60/91-ओ० एन० जी० डी०-4-अपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पञ्चात् आयोग कहा गया है) आर-28 (अपतट) के 160.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 27 जनवरी, 1992 (27.1.92) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंसों की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

- (क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।
- (ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पाए गए तो आयोग पूर्ण व्योरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (ग) स्वल्प शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—
 - (i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेंसेट पर 314 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
 - (ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में घरे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

स्वल्प शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन और लेखा अधिकारी को की जायेगी।

- (घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा।

- (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 80,000/- रुपये की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

- (च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके

किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—

- (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8 रुपये
- (2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40 रुपये
- (3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये
- (4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये
- (5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये।

- (छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।
- (ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को सौंप किए जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूबैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यय तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।
- (झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और "धा" उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उसका भुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।
- (ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।
- (ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।
- (ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा और बुझकीय आंकड़े यथा भामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- (ढ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं।
- (य) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी बल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण बल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।
- (त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रो-ग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

अनुसूची 'क'

के 160.0 वर्ग

आर-28 (अपतट)/किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक।

प्राईट	अक्षांतर	देशांतर
ए	17° 37' 46"	72° 37' 27"
बी	17° 37' 46"	72° 44' 09"
सी	17° 30' 00"	72° 43' 00"
डी	17° 30' 00"	72° 37' 27"

अनुसूची 'ख'

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण
के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस
क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लीटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैब कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लीटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लीटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्वारा मैं, श्री..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० माटिन
डैस्क अधिकारी

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार आयोग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 4 नवम्बर, 1992

विषय :—भारतीय सार अधिनियम, 1885 की पुनरीक्षा करने और उचित संशोधन के बारे में सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन।

सं० 2-1/91-टी० सी० ओ०—इस मंत्रालय की दिनांक 4 नवम्बर, 1991 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा भारतीय सार अधिनियम, 1885 की पुनरीक्षा करने के लिए गठित समिति ने यह अपेक्षा की कि वह अपनी रिपोर्ट 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर देगी।

2. समिति का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 15-5-1992 और 20-8-1992 की अधि० सं० 2-1/91-टी० सी० ओ० द्वारा तीन महीने और बाद में 31-8-92 तक के लिए बढ़ाया गया था।

3. चूंकि संबंधित कार्य 8 अक्टूबर, 1992 तक पूरा किया जा सका अतः समिति का कार्यकाल उस अवधि तक अर्थात् 8 अक्टूबर, 92 तक बढ़ाया जाता है।

आर० रामानुजम,
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 26th September, 1992

Sub : Electronic Hardware Technology Park (EHTP) scheme. Constitution of the Inter-Ministerial Standing Committee.

No. 15(100)/90-EXPORT—In pursuance of the notification no. 42(N. 8)/92-97 dated 14-9-1992 of the Ministry of Commerce (Govt. of India) on Electronic Hardware Technology Parks (EHTP) Scheme, it has been decided to constitute an inter-Ministerial Standing Committee with the following members:

Chairman

(i) Secretary, Department of Electronics.
Members

(ii) Secretary, Ministry of Commerce or nominee

(iii) Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry or nominee from SIA

(iv) Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance or nominee from customs

(v) Secretary, Department of Economic Affairs Ministry of Finance or nominee from ECB.

(vi) Economic Adviser, Department of Electronics
Member Secretary

(vii) Joint Secretary, I. P. Division, Department of Electronics.

2. The scheme will be administered by the Department of Electronics, Government of India, New Delhi. An application for establishing an area to be designated as EHTP or for setting up a unit within an area designated as EHTP or for setting up an individual unit as an EHTP may be made to the Department of Electronics in the prescribed form.

The Inter-Ministerial Standing Committee will carry out the following functions:

(i) Consider all applications for setting up EHTP and accord necessary approvals of the Govt. of India.

(ii) Lay down guidelines regarding such matters, not specified in the notification no. 42(N. 8)/92-97 dated 14-9-1992 of the Ministry of Commerce but which are necessary for operations of the EHTPs.

(iii) Determine the bonding period for units under the EHTP scheme and consider applications for de-bonding as laid down in the notification no. 42(N.8)/92-97 dated 14-9-1992 of the Ministry of Commerce.

(iv) Resolve all disputes/issues arising out of interpretation/application of EHTP scheme.

4. The Ministerial Standing Committee will meet at regular intervals, atleast twice a month. The Chairman may call additional meetings at his discretion.

5. Inter-Ministerial Standing Committee shall come into force from the date of publication of this notification in the official gazette.

6. This Notification is issued in public interest.

N. GOPALASWAMI, Jt. Secy.

STQC DIRECTORATE

New Delhi, the 3rd November, 1992

No. 14(5)/92-STQC/S&QA.—Department of Electronics have under consideration launching a Quality System Certification Scheme in Electronics Sector. As a step in that direction the Government have approved the Quality System Certification Scheme (SQ Scheme) in Electronics Sector in conformance to ISO-9000 Standards. The STQC Directorate an attached office under the Department of Electronics will function as Certification Body for implementing the scheme with Director General (STQC) Dte. functioning as ex-officio Chairman of the Certification Body which will have a Government Board representing all the interests involved to guide, oversee and take policy decisions with regard to the implementation of the scheme.

A. N. SHARMA, Dy. Director

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 5th November, 1992

No. F. 11(1)/88-CILAS—Where as the Supreme Court Legal Aid Committee was constituted by a Resolution dated 9th July, 1981.

2. AND WHEREAS by the Notification dated 22-11-1991, the present Supreme Court Legal Aid Committee was formed in pursuance of the above Resolution for a period of one year with effect from 1-11-1991 or till the Legal Services Authorities Act, 1987 comes into force, whichever is earlier:

AND WHEREAS the term of the Supreme Court Legal Aid Committee expired on 31-10-1992.

NOW, therefore, the President, in continuation to the Notification of even number dated 22-11-1991, is pleased to extend the term of the present Supreme Court Legal Aid Committee, headed by Mr. Justice P.B. Sawant, Judge, Supreme Court of India, for a further period of one year with effect from 1-11-1992 or till the Supreme Court Legal Aid Committee is constituted in terms of the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987, whichever is earlier.

CH. PRABHAKARA RAO, Special Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 2nd November, 1992

ORDER

Sub. : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for R-28 (offshore) area measuring 160.00 sq. kms.

No. 0-12012/60/91-ONG. D. IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 27th January, 1992 (27-1-1992) for R-28 (Off-shore) area measuring 160.0 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the term and conditions mentioned below :—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

- (i) Rs. 314/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.
- (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

- (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
- (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
- (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
- (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
- (v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal

- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the

exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules 1959.

- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/ or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to off-shore areas as approved by the Central Government.

- (l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

- (n) The entire data is processed in India.

- (o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

- (p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

Geographical coordinates of R-28 (Offshore) area measuring 160.0 sq. kms.

Point	Latitude		Longitude
A	17°	37' 46"	72° 37' 27"
B	17°	37' 46"	72° 44' 09"
C	17°	30' 00"	72° 43' 00"
D	17°	30' 00"	72° 37' 00"

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Metric tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total No. of cubic metres obtained	No. of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

M. MARTIN
Desk Officer

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(TELECOM COMMISSION)

New Delhi-110001, the 4th November, 1992

Sub.: Constitution of a Committee to review the Indian Telegraph Act, 1885 and to recommend suitable amendments.

No. 2-1/91-TCO.—The Committee, constituted to review the Indian Telegraph Act 1885 vide this Ministry's Notifica-

tion of even No. dated the 4th November, 1991 was expected to submit its report within a period of 6 months.

2. The term of Committee was extended by three months and again upto 31-8-92 vide Notification No. 2-1/91-TCO dated 15-5-92 and 20-8-92 respectively.

3. Since the pending work could be completed only on 8-10-1992, the term of the Committee is hereby extended upto that period i.e. 8th October, 1992.

R. RAMANUJAM, Jr. Secy.

